

प्रेस विज्ञप्ति

22 मई, 2018

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :-

मोदी सरकार ने 'जीडीपी' (गैस, डीज़ल, पेट्रोल) पर टैक्स लगाकर आम लोगों को 4 सालों में 10,00,000 करोड़ रु. का चूना लगा दिया

मोदी सरकार की पिपासा कर रही आम जनता के बजट का खून!

कांग्रेस की मांग है कि पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए

पिछले साल जुलाई में कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन लोगों की शांति छीनने वाली मोदी सरकार लगातार ईंधन पर भारी टैक्स वसूल रही है।

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अब तक सबसे ज्यादा हाँ चुकी हैं, जिससे आम जनता, किसानों और मध्यम वर्ग का बजट गड़बड़ा गया है। डीज़ल का मूल्य आसमान छूते हुए 68.08 रु प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जिससे किसानों की जीविका को बहुत गहरा धक्का लगा है और खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने तय हैं। पिछले 9 दिनों में डीज़ल की कीमतों में 2.15 रु. प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हुई है। पेट्रोल की कीमतें प्रतिदिन बढ़ाने के मोदी सरकार के फैसले ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 76.87 रु. प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं और पिछले नौ दिनों में ये लगातार 2.24 रु. प्रति लीटर बढ़ी हैं।

महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश में तो ये कीमतें और भी ज्यादा हैं। देश की वित्तीय राजधानी, मुंबई में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 85 रु प्रति लीटर से भी ज्यादा होने का रिकॉर्ड बना रही हैं।

Petrol price (in ₹ per litre)				
	22-May	21-May	13-May	31-Dec
Delhi	76.57	76.24	74.63	69.97
Kolkata	79.24	78.91	77.32	72.72
Mumbai	84.4	84.07	82.48	77.87
Chennai	79.47	79.13	77.43	72.53

Diesel price (in ₹ per litre)				
	22-May	21-May	13-May	31-Dec
Delhi	68.08	67.82	65.93	59.64
Kolkata	70.63	70.37	68.63	62.3
Mumbai	72.48	72.21	70.2	63.27
Chennai	71.87	71.59	69.56	62.83

(Source: iocl.com)

- फायदे आम नागरिकों को देने की बजाए भाजपा सरकार पेट्रोल-डीज़ल पर टैक्स लगाकर अपना खजाना भर रही है।
- मई, 2014 से पेट्रोल की एक्साइज़ ड्यूटी में प्रतिशत वृद्धि – 211.7 प्रतिशत।
- मई, 2014 में यह केवल 9.2 रु./लीटर थी, जबकि आज 19.48 रु./लीटर है।
- मई, 2014 से डीज़ल की एक्साइज़ ड्यूटी में प्रतिशत वृद्धि – 443.06 प्रतिशत।
- मई, 2014 में यह केवल 3.46रु./लीटर थी, जो आज 15.33 रु./लीटर है।
- भाजपा के सत्ता स्थालने के बाद केंद्रीय एक्साइज़ ड्यूटी 12 बार बढ़ाई गई है।



तेल की कीमतें – भारत के लिए बुरे दिनों की शुरुआत!

26 मई, 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें 30 प्रतिशत से ज्यादा गिरी हैं। भाजपा सरकार ने पेट्रोल/डीज़ल पर (2017–18 की दूसरी तिमाही तक) विभिन्न केंद्रीय टैक्स लगाकर 7.35 लाख करोड़ रु0 सरकारी खजाने में भर लिए। यह सारा पैसा कहां गया?

हम भाजपा को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने ‘अच्छे दिन’ के बायदे पर अपनी सरकार बनाई थी, जिसके लिए पेट्रोल की कीमतों में कमी करना तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकना बहुत आवश्यक है। भाजपा सरकार ने हर मोर्चे पर देश की जनता को निराश किया है।

मोदी सरकार के सत्ता सम्हालने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें 73 प्रतिशत से अधिक गिरीं, लेकिन इसके विपरीत पेट्रोल एवं डीज़ल की कीमतों में क्रमशः 108 प्रतिशत और 123 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई (26 मई, 2014 की दरों की तुलना में)। इससे भाजपा सरकार का आम जनता के प्रति विरोधी रवैया प्रदर्शित होता है।

मई, 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल 107.57 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था, जो घटकर 79 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गया; लेकिन दिल्ली में पेट्रोल एवं डीज़ल का मूल्य क्रमशः 71.41 रु. और 55.49 रु. से बढ़कर 76.87 रु. और 68.08 रु. हो गया।

भारत में पेट्रोल और डीज़ल क्रमशः 76 रु.–86 रु. एवं 68 रु.–75 रु. के बीच हैं; जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल क्रमशः 50.67 रु. और 57.06 रु.; श्री लंका में क्रमशः 49.67 रु. एवं 40.33 रु.; नेपाल में क्रमशः 66.69 रु. एवं 54.73 रु. और बांग्लादेश में क्रमशः 68.47 रु. और 51.73 रु. प्रति लीटर हैं।

श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम जनता का विश्वास तोड़ा है। सरकार ईंधन की बढ़ती कीमतों को रोकने में विफल साबित हो गई है और आम नागरिकों की जेब काटकर सरकारी खजाने भर रही है।

हमारी सीधी सी मांग है कि केंद्र सरकार पेट्रोल एवं डीज़ल पर तुरंत केंद्रीय एक्साईज़ में कटौती करे, भाजपा शासित राज्यों की सरकारें पेट्रोल व डीज़ल पर वैट एवं अन्य टैक्सों को कम करें तथा पेट्रोल–डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए।